



- केन्द्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से कृषि-पारिस्थितिकी पर्यटन पहल द्वीप एग्रो-इको वॉक का उद्घाटन।
- द्वीपसमूह में विद्युत वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण की दिशा में मुख्य सचिव ने पुनरोद्धार वितरण क्षेत्र योजना परियोजना के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
- अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नौ महीने तक फंसे रहने के बाद पृथ्वी के लिए वापसी यात्रा शुरू की।
- अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से तीन दूरस्थ लुक आउट पोस्ट में सौर पैनल स्थापित।



केन्द्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि विज्ञान केन्द्र, सीपीघाट में आज मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने कृषि-पारिस्थितिकी पर्यटन पहल द्वीप एग्रो-इको वॉक का उद्घाटन किया। इसके अलावा गाराचरमा स्थित अनुसंधान परिसर में दो दिवसीय किसान मेला-सह-प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि और पशुपालन सचिव पल्लवी सरकार भी उपस्थित थी। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कृषि, बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ाने में क्यारी के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने शहरी निवासियों के सामने छोटे किचन गार्डन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। मुख्य सचिव ने सिपीघाट फार्म में एग्रो-इको वॉक पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि बेहतर बाजार स्वीकृति और पर्यटन क्षमता के लिए जैविक उत्पादों की गुणवत्ता की ब्रांडिंग पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने द्वीपसमूह में किसानों की आय को बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। मुख्य सचिव ने सभी स्टॉलों का दौरा किया और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की। इसमें क्यारी, कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन, नाबार्ड, एस बी आई, एस एच जी, पी पी वी एफ आर ए और निजी फर्मों के तकनीकी प्रदर्शनों सहित कुल बाईस स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर तीन जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह किसानों को कृषि प्रौद्योगिकियों और उद्यमशीलता उपलब्धियों के सफल कार्यान्वयन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लगभग दो सौ पचास किसानों, कृषि महिलाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया।



अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में विद्युत वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण की दिशा में प्रशासन के मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने पुनरोद्धार वितरण क्षेत्र योजना परियोजना के अंतर्गत श्री विजयपुरम में पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक लागत के दो समझौतों और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तिरपन दशमलव दो छः करोड़ रुपये की लागत वाली स्मार्ट मीटरिंग परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन, दो सौ सैंतालीस दशमलव एक दो करोड़ रुपये की लागत वाली हानि न्यूनीकरण परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन और दो सौ आठ दशमलव शून्य चार करोड़ रुपये की लागत वाले समझौते पर विद्युत सचिव और पावर ग्रिड के वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। आर डी एस एस के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा पावर ग्रिड को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। इसका उद्देश्य विद्युत वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ और आधुनिक बनाना है। इस समझौते से द्वीपसमूह में विद्युत वितरण प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विद्युत गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार आएगा। यह योजना तीन प्रमुख घटकों हानि में कमी, स्मार्ट मीटरिंग और द्वीपों का अंतर्संबंध पर केंद्रित है। इस कार्य में पुराने और अकुशल ट्रांसफार्मरों को बदलना, नए सब-स्टेशनों का निर्माण, मौजूदा सब-स्टेशनों का विस्तार, पुराने और जर्जर कंडक्टरों को कवर कंडक्टरों से बदलना, फीडरों का विभाजन, अतिरिक्त एचटी लाइनों का निर्माण और ट्रांसमिशन लाइनों को मजबूत करना शामिल होगा। इससे उपभोक्ताओं को सटीक बिलिंग, वास्तविक समय में ऊर्जा उपयोग ट्रेकिंग और बिजली की खपत में बढ़ी हुई पारदर्शिता का लाभ मिलेगा। इस परियोजना में बम्बूपलाट, बकुलतला, रंगत, मायाबंदर और डिगलीपुर में पांच प्रमुख सब-स्टेशनों की परिकल्पना की गई।



अमरीका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि नौ महीने से अधिक समय से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स आज रात पृथ्वी पर लौट आएंगे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान दोनों को लेकर कल सुबह तीन बजकर सत्ताईस मिनट पर पृथ्वी पर उतरेगा। नासा की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ड्रैगन अंतरिक्ष यान को पृथ्वी पर वापसी के लिए तैयार किया जा रहा है। यान के लिए स्थितियां भी अनुकूल हैं। ऐसी संभावना है कि यह यान दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा तट के पास समुद्र में उतरेगा। इसके अलावा ड्रैगन अंतरिक्ष यान नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव को भी वापस लेकर आएगा।



कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह के निर्देश पर पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशन नीति के साथ-साथ पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। विभाग ने पेंशनभोगियों को एक ही पोर्टल से निर्बाध बैंकिंग सेवाएं प्रदान

<><><><><><><>

<><><><><><><>

<><><><><><><>

<><><><><><><>